>

Title: Regarding Smart city project of Ajmer city, Rajasthan - Laid

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): केन्द्र सरकार ने देश के 100 नगरों को स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का कार्य प्रारम्भ किया है, जिसमें राजस्थान प्रदेश के जयपुर, उदयपुर कोटा एवं अजमेर को चयन किया गया और अमेरिका सरकार ने भारत के जिन 3 नगरों को स्मार्ट सिटी बनाने हेतु निर्णय लिया है, उसमें अजमेर भी शामिल है । योजना के तहत अजमेर शहर के लिए अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की स्थापना सितम्बर, 2016 में कर जनवरी 2017 में कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसके अन्तर्गत 89 कार्यो/प्रोजेक्ट का चयन किया गया जिसमें प्रमुखतया सीवरेज, पेयजल आपूर्ति, ड्रेनेज, पार्को का विकास, सौर उर्जा के कार्य एल ई डी लाईट्स, स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन, एलीवेटेड रोड, आनासागर झील का विकास एवं सौन्दर्गीकरण, सुभाष उद्यान का पुनरोद्धार, धरोहर संरक्षण एवं पर्यटन विकास, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कार्य, साईकिल शेयरिंग व ओपन एयर जिम, स्मार्ट क्लासेज, आनासागर स्केप चैनल में सुधार आदि कार्य सम्मिलित किए गए । उक्त प्रस्तावित कार्यों हेतु लगभग 1948 करोड़ रूपये का बजट भी स्वीकृत हो गया है, तत्पश्चात इसके लिए खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के माध्यम से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सल्टेन्सी का कार्य स्पेन की एक फर्म को दिनांक 1 5.02.2017 को आबंटित किया गया, लेकिन निविदा की शर्तों के अनुसार कार्य करने में विफल रहने पर उक्त फर्म को कार्यादेश को राज्य सरकार ने अपने स्तर पर निर्णय लेकर दिनांक 09.06 2017 को निरस्त कर दिया । तब से लेकर अभी तक बिना कन्सल्टेन्सी कम्पनी के उक्त प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना संभव नहीं लग रहा है । वहीं दूसरी ओर स्थानीय प्रशासनिक उदासीनता के चलते उक्त 89 कार्यों में से अभी तक 6 प्रोजेक्ट ही पूरे हुए हैं, तो 24 कार्य गत 2-3 वर्षों से अण्डर प्रोसेस ही चल रहे हैं । वर्तमान में उक्त योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का दायित्व जिला कलक्टर अजमेर एवं उप मुख्य

कार्यकारी अधिकारी का कार्य कमिशनर नगर निगम के पास है । दोनों की अधिकारी अपने विभागीय कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता के चलते इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं । अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत मेरे संसदीय क्षेत्र अजमेर शहर में उक्त योजना के सफल क्रियानवयन हेतु एक पृथक से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति कराने का श्रम करावें ताकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को समुचित गति मिल सके और प्रोजेक्ट शीघ्र एवं समय पर पूर्ण हो सके ।